नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 136
दि. 18.02.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

रहस्य से घिरा अजित पवार का विमान हादसा: ब्लैक बॉक्स खोलेगा सच, जांच में विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति और देशभर में उस समय सनसनी फैल गई जब वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई। यह हादसा केवल एक तकनीकी दुर्घटना नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे संभावित कारणों, तकनीकी खामियों और साजिश की आशंकाओं को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सौंप दी गई है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि हादसे की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी और सभी संदेहों का समाधान होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, यह दुर्घटना 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती क्षेत्र में हुई थी, जब लीयरजेट-45 विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे ने न केवल राजनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी, बल्कि विमान सुरक्षा और वीआईपी उड़ानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर बहस शुरू कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस दुर्घटना की जांच पूरी तरह तकनीकी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप की जाएगी, ताकि निष्पक्ष और तथ्य आधारित निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। जांच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी विमान में लगे फ्लाइट रिकॉर्डर हैं, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इनमें डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर शामिल होते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर विमान की

गति, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, नियंत्रण प्रणाली और अन्य तकनीकी पहलुओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड करता है। दूसरी ओर, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर पायलट और सह-पायलट के बीच हुई बातचीत, अलर्ट सिस्टम की चेतावनियां और कॉकपिट के भीतर की ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई थी, जिससे रिकॉर्डर अत्यधिक तापमान और क्षति के संपर्क में आ गए। इसके बावजूद, जांच टीम ने डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से महत्वपूर्ण डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया है। यह डेटा दुर्घटना से पहले विमान की तकनीकी स्थिति और उड़ान के दौरान हुई घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।

हालांकि, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर से डेटा निकालने की प्रक्रिया अभी जारी है। चूंकि यह उपकरण अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसलिए इसकी तकनीकी जांच के लिए विदेशी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। यह विशेषज्ञ उसी देश से हैं जहां यह उपकरण निर्मित किया गया था। इससे उम्मीद की जा रही है कि कॉकपिट में दुर्घटना से पहले क्या हुआ, पायलट ने क्या प्रतिक्रिया दी और क्या कोई तकनीकी चेतावनी मिली थी, इन सभी सवालों के जवाब मिल सकेंगे।

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल दुर्घटना के कारणों का पता लगाना ही नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा सुधारों की पहचान करना भी है। जांच एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की अफवाहों और अटकलों से बचें।

इस हादसे के बाद राजनीतिक स्तर पर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और अजित पवार के परिवार के सदस्यों ने इस घटना को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनके भतीजे और विधायक रोहित पवार ने सार्वजनिक रूप से यह आशंका जताई कि इस दुर्घटना के पीछे साजिश भी हो सकती है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच उच्च स्तरीय और विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा की जाए, ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके। इसी क्रम में महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यह घटना अत्यंत गंभीर है और इसकी गहन और निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि किसी भी संभावित साजिश या लापरवाही का पता लगाया जा सके।

यह पहली बार नहीं है जब किसी वीआईपी विमान दुर्घटना ने इस तरह के सवाल खड़े किए हैं। अतीत में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां तकनीकी खराबी, मानवीय त्रुटि या अन्य कारणों से विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। इसलिए इस मामले में जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे तकनीकी तथ्यों के आधार पर वास्तविक कारणों की पहचान करें और किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करें।

समुद्र के रास्ते संदिग्ध रसायन की तस्करी नाकाम, दो ईरानी नागरिक गिरफ्तार

(जीएनएस)। देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सतर्कता और मुस्तैदी का उदाहरण बनकर सामने आई है, जब गुजरात तट के पास एक बड़े संयुक्त अभियान में सुरक्षा एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदिग्ध रासायनिक पदार्थ की तस्करी की कोशिश को विफल कर दिया। इस कार्रवाई में दो ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 200 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध रासायनिक पदार्थ बरामद किया गया। यह ऑपरेशन देश की सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता, खुफिया तंत्र की मजबूती और समुद्री सीमाओं की प्रभावी निगरानी का स्पष्ट प्रमाण माना जा रहा है। यह कार्रवाई गुजरात एटीएस और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से की गई। सुरक्षा एजेंसियों को पहले से खुफिया सूचना मिली थी कि समुद्र के रास्ते भारत के जलक्षेत्र में एक संदिग्ध रासायनिक पदार्थ की खेप लाई जा रही है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक विशेष अभियान की योजना बनाई गई और समुद्र में निगरानी तेज कर दी गई। यह ऑपरेशन गुजरात तट से लगभग 140 समुद्री मील दूर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास चलाया गया, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है।

अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध स्पीड बोट को रोकने का प्रयास किया। प्रारंभिक जांच में बोट पर मौजूद दोनों व्यक्ति

ईरान के नागरिक पाए गए। जब उनकी नाव की तलाशी ली गई, तो उसमें 203 पैकेट मिले, जिनमें सफेद पाउडर जैसा पदार्थ भरा हुआ था। इन पैकेटों का कुल वजन 200 किलोग्राम से अधिक बताया गया है। यह बरामदगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में संदिग्ध रासायनिक पदार्थ का देश में प्रवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता था।

गुजरात एटीएस के उप महानिरीक्षक सुनील जोशी ने इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करीब आठ से दस घंटे तक चला, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी सतर्कता और रणनीति के साथ संदिग्ध नाव को रोका और उसमें मौजूद व्यक्तियों को हिरासत में लिया। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह के मामलों में समय पर कार्रवाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देरी होने पर संदिग्ध सामग्री देश के अंदर पहुंच सकती है और उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि बरामद रासायनिक पदार्थ को कथित तौर पर ईरान से लाया जा रहा था और इसे भारत के पंजाब राज्य में किसी व्यक्ति को सौंपने की योजना थी। हालांकि, अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह पदार्थ किस प्रकार का है और इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था। इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए बरामद पैकेटों को फोरेंसिक जांच के लिए पोरबंदर स्थित तटरक्षक स्टेशन भेजा गया है।

फोरेंसिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह पदार्थ किसी औद्योगिक उपयोग का है, नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाना था या फिर इसका संबंध किसी अन्य अवैध गतिविधि से है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही हैं और हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए दोनों ईरानी नागरिकों से पूछताछ जारी है, ताकि इस तस्करी नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों और इसके पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाया जा सके।

यह घटना एक बार फिर इस बात की ओर संकेत करती है कि समुद्री मार्ग तस्करों के लिए एक प्रमुख माध्यम बना हुआ है। भारत की लंबी समुद्री सीमा होने के कारण इसकी निगरानी करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि, भारतीय तटरक्षक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपनी निगरानी और तकनीकी क्षमता को मजबूत कर रही हैं, जिससे इस प्रकार की गतिविधियों को समय रहते रोका जा सके।

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की तस्करी केवल आर्थिक अपराध नहीं होती, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। संदिग्ध रासायनिक पदार्थ का उपयोग अवैध गतिविधियों, नशीले पदार्थों के निर्माण या अन्य खतरनाक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोकना अत्यंत आवश्यक है।

इस सफल ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर प्रकार के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खुफिया तंत्र की सतर्कता और सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई के कारण एक बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सका। यह कार्रवाई न केवल देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

लोकतंत्र पर सवाल या सियासी रणनीति? निर्वाचन आयोग पर ममता का तीखा हमला

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे 'तुगलकी आयोग' करार दिया। उनके इस बयान ने न केवल राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि देशभर में चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर नई बहस को भी जन्म दे दिया है। कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में व्यापक स्तर पर हेरफेर किया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर रहा है और राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला होती है और यदि उसी में छेड़छाड़ की जाए, तो चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। उनका कहना था कि आम नागरिकों का वोट देने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से एक है और इसे किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि इस प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग किया गया है। उनके अनुसार, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एक

आईटी सेल की महिला पदाधिकारी ने एआई तकनीक का उपयोग कर लगभग 58 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटवाने में भूमिका निभाई। उन्होंने इस आरोप को लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि तकनीक का उपयोग पारदर्शिता और सुविधा के लिए होना चाहिए, न कि लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने के लिए।

ममता बनर्जी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा तार्किक विसंगतियों और तकनीकी कारणों का हवाला देकर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि आम नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे वे किसी अपराध के दोषी हों। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत किया जा रहा है, ताकि राजनीतिक लाभ हासिल किया जा सके। उन्होंने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के मतदाताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाई से राज्य के लोगों में असुरक्षा और अविश्वास का माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और यदि वही संस्था सवालों के घेरे में आ जाए, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

निर्वाचन आयोग द्वारा निलंबित किए गए सात सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों का बचाव करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों के साथ खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि राज्य के अधिकारियों के साथ अन्याय किया गया, तो राज्य सरकार उनकी पूरी रक्षा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों को पदावनत किया गया है, उन्हें राज्य सरकार पदोन्नत करने पर विचार करेगी। उनका यह बयान राज्य प्रशासन और निर्वाचन आयोग के बीच बढ़ते टकराव का संकेत माना जा रहा है।

ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न दबाव और चिंता के कारण राज्य में 160 लोगों की जान चली गई। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इस बयान ने पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना होना चाहिए, न कि लोगों को मानसिक तनाव और भय में डालना।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार के आरोप चुनावी माहौल में अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री इस स्तर का आरोप लगाता है, तो इसका प्रभाव व्यापक होता है। इससे न केवल राज्य की राजनीति प्रभावित होती है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है और इस पर किसी भी प्रकार का संदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति और अधिक तीखी हो सकती है। मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया और तकनीक के उपयोग जैसे मुद्दे राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बने रहेंगे। इस बीच, आम नागरिकों की अपेक्षा यही है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे, ताकि लोकतंत्र की मूल भावना सुरक्षित रह सके।

लोकतंत्र का महापर्व और चुनाव आयोग की तैयारी: असम में निष्पक्ष चुनाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

(जीएनएस)। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां चुनाव केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। चुनाव वह माध्यम है जिसके जरिए आम नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनता है और सरकार के गठन में अपनी निर्णायक भूमिका निभाता है। इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग लगातार राजनीतिक दलों, प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों के साथ संवाद करता रहता है। इसी क्रम में असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव आयोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

यह बैठक गुवाहाटी में आयोजित की गई, जहां ज्ञानेश कुमार, जो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ने इस बैठक की अध्यक्षता की। उनके साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित रहे। इस बैठक में असम की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और आगामी चुनावों को लेकर अपने सुझाव और चिंताएं आयोग के सामने रखीं।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी असम विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने की तैयारी को मजबूत करना था। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया कि चुनाव को एक या अधिकतम दो चरणों में आयोजित किया जाए। उनका मानना है कि यदि चुनाव कम चरणों में होंगे, तो इससे प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक सरल होगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा। राजनीतिक दलों का यह सुझाव कई महत्वपूर्ण कारणों पर आधारित है। पहला कारण यह है कि लंबे समय तक चलने वाले चुनावों से राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। जब चुनाव कई चरणों में आयोजित होते हैं, तो सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों को लंबे समय तक चुनाव ड्यूटी में लगे रहना पड़ता है, जिससे अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा, लंबी चुनाव प्रक्रिया से राजनीतिक माहौल भी लंबे समय तक तनावपूर्ण बना रहता है, जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव डाल सकता है।

चुनाव आयोग के लिए यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह आयोग को राजनीतिक दलों की वास्तविक चिंताओं और अपेक्षाओं को समझने का अवसर प्रदान करती है। चुनाव आयोग का मुख्य दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र हों। इसके लिए आयोग राजनीतिक दलों, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार संवाद करता रहता है और उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपनी रणनीति तैयार करता है।

इस प्रकार की बैठकों का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बनाए रखना होता है। जब राजनीतिक दलों को यह महसूस होता है कि उनकी बातों को सुना जा रहा है और उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है, तो इससे चुनाव प्रक्रिया के प्रति उनका विश्वास मजबूत होता है। यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी पक्ष चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और विश्वसनीय मानें।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नया रणवीर: कैसे एआई ने सीमा पर भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाया

(जीएनएस)। आधुनिक युद्ध अब केवल बंदूकों, टैंकों और सैनिकों की संख्या से नहीं जीते जाते, बल्कि सूचना, तकनीक और समय पर लिए गए निर्णयों से जीते जाते हैं। 21वीं सदी का युद्धक्षेत्र तेजी से बदल रहा है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली हथियार बनकर उभरी है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण खुलासे ने यह साबित कर दिया है कि एआई अब केवल उद्योग, चिकित्सा या व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इंडियन आर्मी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया कि एआई की मदद से सीमा पर एक संभावित घुसपैठ को समय रहते पहचान लिया गया और उसे पूरी तरह विफल कर दिया गया। यह घटना केवल एक सैन्य सफलता नहीं है, बल्कि यह भविष्य के युद्ध की दिशा को भी स्पष्ट करती है। यह जानकारी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान सामने आई, जहां लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा, जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड के कमांडर-इन-चीफ हैं, ने विस्तार से बताया कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद एआई ने एक बड़े खतरे को टालने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह घटना उस समय की है जब वे अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्र में तैनात थे, जहां सीमा सुरक्षा हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है।

सीमा पर स्थित तवांग और उसके आसपास का क्षेत्र रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास स्थित है, जो भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा का कार्य करती है। इस क्षेत्र में अक्सर तनाव बना रहता है और दोनों देशों की सेनाएं अत्यधिक सतर्क रहती हैं। ऐसे संवेदनशील वातावरण में हर छोटी गतिविधि पर नजर रखना आवश्यक होता है, लेकिन यह कार्य मानव क्षमता से परे होता है। यहीं पर एआई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। एआई की सबसे बड़ी ताकत उसकी विश्लेषण क्षमता है। यह हजारों सेंसर, कैमरों और अन्य निगरानी उपकरणों से आने वाले डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है और उसमें से असामान्य गतिविधियों की पहचान कर सकता है। जिस घटना का उल्लेख किया गया, उसमें एआई सिस्टम ने संदिग्ध गतिविधियों के पैटर्न को पहचान लिया और समय रहते सेना को चेतावनी दे दी। यह चेतावनी इतनी सटीक थी कि सेना ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और अपने सैनिकों को सही स्थानों पर तैनात कर दिया। इस समयबद्ध प्रतिक्रिया के कारण घुसपैठ की कोशिश पूरी तरह विफल हो गई और किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं हुआ।

यह घटना इस बात का प्रमाण है कि एआई केवल एक सहायक उपकरण नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक निर्णय लेने वाला साझेदार बन चुका है। पहले जहां सैनिकों को अपने अनुभव और सीमित जानकारी के आधार पर निर्णय लेना पड़ता था, वहीं अब एआई उन्हें सटीक और वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। इससे निर्णय अधिक प्रभावी और सुरक्षित हो जाते हैं। यह तकनीक न केवल दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाती है, बल्कि यह यह भी अनुमान लगा सकती है कि दुश्मन आगे क्या कदम उठा सकता है।

एआई की यह क्षमता भविष्यवाणी करने की है, जो इसे अत्यंत मूल्यवान बनाती है। यह पिछले डेटा और वर्तमान गतिविधियों का विश्लेषण करके संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगा सकती है। इससे सेना को पहले से तैयारी करने का अवसर मिलता है और अचानक होने वाले हमलों की संभावना कम हो जाती है। यह एक प्रकार से युद्ध के नियमों को बदल रहा है, जहां अब केवल प्रतिक्रिया देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पहले से अनुमान लगाकर तैयारी करना आवश्यक हो गया है। इस तकनीक का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सैनिकों की सुरक्षा को बढ़ाता है। युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा नुकसान मानव जीवन का होता है। यदि एआई समय रहते खतरे की पहचान कर लेता है, तो सैनिकों को जोखिम भरे क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता कम हो जाती है।

संपादकीय

शिखर सम्मेलन से दुनिया में भारतीय

तकनीकी युग में वह राष्ट्र ही भविष्य का नेतृत्व करता है, जो समय रहते परिवर्तन की दिशा और उसकी गति को पहचान लेता है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के रूप में दुनिया एक ऐसी क्रांति के दौर से गुजर रही है, जो न केवल अर्थव्यवस्था और उद्योग की संरचना को बदल रही है, बल्कि समाज, शासन और मानव जीवन के हर क्षेत्र को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। ऐसे समय में भारत द्वारा वैश्विक एआई समिट आयोजित करने का निर्णय केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिक कदम है, जो आने वाले दशकों में देश की भूमिका और पहचान को निर्धारित करेगा। यह इस बात का संकेत है कि भारत केवल तकनीकी का उपभोक्ता नहीं रहना चाहता, बल्कि तकनीकी नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है।

देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित यह पांच दिवसीय सम्मेलन, जिसमें सौ से अधिक बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीस के करीब देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 135 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी हो रही है, इस आयोजन की वैश्विक महत्ता को स्पष्ट करता है। यह केवल आंकड़ों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह विश्वास का प्रमाण है कि दुनिया भारत को एआई के क्षेत्र में एक विश्वसनीय और जिम्मेदार शक्ति के रूप में देख रही है। विशेष रूप से भारत मंडपम जैसे आधुनिक और भव्य स्थल पर इस आयोजन का होना भारत की तकनीकी क्षमता और संगठनात्मक दक्षता का प्रतीक है।

भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसका युवा जनसंख्या आधार है। दुनिया में सबसे अधिक युवाओं वाले देश के रूप में भारत के पास वह मानव संसाधन है, जो एआई जैसी उन्नत तकनीकों को विकसित करने, अपनाने और आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। आज भारत में लाखों युवा डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और एआई से जुड़े क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह केवल व्यक्तिगत करियर का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास का आधार बन रहा है। जिस तरह औद्योगिक क्रांति ने 19वीं सदी में यूरोप को बदल दिया था, उसी तरह एआई क्रांति 21वीं सदी में भारत को वैश्विक नेतृत्व की स्थिति में ला सकती है।

इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत एआई को केवल आर्थिक लाभ का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाना चाहता है। एआई का उपयोग स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने, कृषि को अधिक उत्पादक बनाने और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एआई आधारित सिस्टम किसानों को मौसम की सटीक जानकारी दे सकते हैं, डॉक्टरों को रोगों का शीघ्र और सटीक निदान करने में सहायता कर सकते हैं, और छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा अनुभव प्रदान कर सकते हैं। इससे न केवल जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि सामाजिक असमानता को भी कम किया जा सकेगा। आज दुनिया में एआई के विकास और उपयोग को लेकर असमानता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विकसित और धनी देश इस तकनीक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे विकासशील देशों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। ऐसे समय में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें एआई का उपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और समावेशिता के आधार पर किया जाए। भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि एआई केवल कुछ कंपनियों या देशों का उपकरण न बने, बल्कि यह पूरी मानवता के विकास का माध्यम बने। इस सम्मेलन में लगभग तीन लाख लोगों का पंजीकरण होना इस बात का प्रमाण है कि एआई को लेकर लोगों में कितना उत्साह और जिज्ञासा है। यह केवल विशेषज्ञों और कंपनियों तक सीमित विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह आम लोगों के जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। यह आवश्यक है कि इस उत्साह को सही दिशा दी जाए और युवाओं को उचित प्रशिक्षण और अवसर प्रदान किए जाएं। इसके लिए सरकार, शिक्षा संस्थानों और उद्योगों को मिलकर काम करना होगा। हाल के वर्षों में भारत ने एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। देश में विशाल डेटा संसाधन उपलब्ध हैं, जो एआई के विकास के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा, सरकार ने एआई अनुसंधान, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। भारत का लक्ष्य केवल एआई तकनीक का उपयोग करना नहीं, बल्कि उसे विकसित करना और वैश्विक स्तर पर उसका नेतृत्व करना है। यह सम्मेलन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत की प्रतिबद्धता और क्षमता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। हालांकि, एआई के साथ कई चुनौतियां और जोखिम भी जुड़े हुए हैं। एआई का दुरुपयोग गलत सूचना फैलाने, साइबर अपराध बढ़ाने और लोगों की निजता का उल्लंघन करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, यह भी चिंता है कि एआई के कारण कई पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो सकती हैं।

नये परिदृश्य में हसीना के प्रत्यर्पण का यक्ष प्रश्न

"भारत ने आम तौर पर शरणार्थियों को वापस न भेजने (नॉन-रिफाउलमेंट) की नीति अपनाई हुई है। इसी नीति के तहत, दलाई लामा जैसे प्रमुख राजनीतिक शरणार्थियों को ऐतिहासिक रूप से संरक्षण दिया गया है। हालांकि, भारत 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।

शेख हसीना, जो 5 अगस्त, 2024 को हिंसक प्रदर्शनकारियों से जान बचाते हुए ढाका से गाजियाबाद के लिए एक सीक्रेट फ्लाइट से भागी थीं, अभी फांसी से दूर हैं, और नई दिल्ली निर्वासन में रह रही हैं। शेख हसीना का सवाल विक्रम और बेताल की तरह मोदी सरकार के कंधे पर सवार है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को 'एआई समिट' में उपस्थित रहना था, इसलिए, तारिक़ रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने ढाका, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को भेजा। बांग्लादेश की तरफ से उन्हें सौंपने के बार-बार अनुरोध के बावजूद भारत में हसीना की मौजूदगी पिछले 18 महीनों में दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह रही है।

भले ही भारत, ढाका के साथ 'पोस्ट हसीना पार्टनरशिप' बनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा, कि वे ऐसे हालात की कल्पना नहीं कर सकते, जिसमें नई दिल्ली पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सज़ा का सामना करने के लिए बांग्लादेश को सौंप दे। ढाका रह चुके भारत के पूर्व हाई कमिश्नर पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा, 'नई दिल्ली उन्हें मौत की तरफ कैसे धकेल सकती है?'

हसीना, बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं, वो शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। शेख हसीना कोई पहली बार भारत में शरणागत नहीं हुई हैं। 15 अगस्त, 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की ढाका में उनके धानमंडी स्थित घर पर मिलिट्री तख्तापलट के

दौरान हत्या कर दी गई थी। इस हमले में उनकी पत्नी, तीन बेटे और दूसरे रिश्तेदार मारे गए थे। उनकी दो बेटियां संयोगवश बच गयीं, जो घटना के समय जर्मनी में थीं। उनमें एक शेख हसीना और दूसरी शेख़ रेहाना थीं। हसीना के पास अपने पति एमए वाजेद मियां के साथ भारत में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वर्ष 1975 से 1981 तक वे सभी दिल्ली के पंडारा रोड में एक नकली पहचान के साथ रहे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार, हसीना के 'निर्वासन पार्ट-टू' को लेकर दुविधा में है। हसीना ने 2022 के इंटरव्यू में मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद के पलों को याद करते हुए कहा, 'मिसेज इंदिरा गांधी ने तुरंत जानकारी भेजी, कि वह हमें सुरक्षा और पनाह देना चाहती हैं।' दिल्ली आने के बाद, हसीना इंदिरा गांधी से मिलीं, तभी उन्हें अपने परिवार के 18 सदस्यों की हत्या के बारे में पता चला।

हसीना ने 2022 में न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बताया, 'इंदिरा गांधी ने हमारे लिए सारे इंतज़ाम किए। मेरे पति के लिए नौकरी भी।' दिल्ली में हसीना पहले 56 रिंग रोड, लाजपत नगर-3 में रहती थीं, फिर दिल्ली के पंडारा रोड के घर में शिफ्ट हो गईं। छह साल बाद, 17 मई, 1981 को, हसीना बांग्लादेश लौटीं। वापसी के बाद देश पर कब्ज़ा कर चुकी मिलिट्री सरकार के खिलाफ एक लंबी और मुश्किल लड़ाई की शुरुआत की। करप्शन के आरोपों में जेल के बावजूद, हसीना डटी रहीं। आखिरकार, 1996 में शेख़ हसीना सत्ता में आईं, और पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं।

लेकिन उस कालखंड से इस समय अलग परिस्थितियां हैं। पीएम मोदी बांग्लादेश के सन्दर्भ में अपनी पूर्ववर्ती इंदिरा गांधी की राह पर चले ज़रूर, मगर इसके अंजाम का आकलन मोदी के रणनीतिकार सही से नहीं कर पाए। वर्ष 2013 में भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी। और 2016 में इसमें बदलाव किया गया था, जो कम से कम एक साल की जेल की सज़ा वाले अपराधों के दोषी या अभियुक्तों की अदला-बदली की अनुमति देती है। इसमें आतंकवाद, ट्रैफिकिंग और ऑर्गनाइज़्ड क्राइम जैसे अपराध शामिल हैं, लेकिन यदि कोई राजनीतिक क़ैदी है, तो उसके प्रत्यर्पण से मना करने की सहूलियत भी संधि में है। 11 पेज की संधि के अनुच्छेद 6-7 और 8 को ध्यान से पढ़ा जाये, तो शेख हसीना को आपराधिक धाराओं से भी छूट मिल जाती है। भारत इन्हीं धाराओं के आधार पर शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण से मना करने की स्थिति में है। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और उनके समकक्ष डॉ. मोहिनुद्दीन ख़ान आलमगीर अभी जीवित हैं।

बहरहाल, 17 नवंबर, 2025 को 453 पेज के फैसले में, बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने शेख़ हसीना और दो सह-आरोपियों को दो अलहदा मामलों में मौत की सजा सुनाई थी। उन्हें पिछले साल 5 अगस्त को ढाका के चंखारपुल में छह निहत्थे प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या करने के आरोप संख्या 4 के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी। आरोप संख्या 5 के तहत, आरोपियों पर उसी दिन अशुलिया में छह छात्र प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आरोप था, जिनमें से पांच को बाद में जला दिया गया था, जबकि छठे को कथित तौर पर जिंदा रहते हुए आग लगा दी गई थी। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई, जबकि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, जो सरकारी गवाह बन गए थे, को इस मामले में पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। भारत का कहना है, कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश के आग्रह की जांच कर रहा है।

क्या भारत ने पहले कभी किसी राजनीतिक शरणार्थी का प्रत्यर्पण किया है? भारत ने आम तौर पर शरणार्थियों को वापस न भेजने (नॉन-रिफाउलमेंट) की नीति अपनाई हुई है। इसी नीति के तहत, दलाई लामा जैसे प्रमुख राजनीतिक शरणार्थियों को ऐतिहासिक रूप से संरक्षण दिया गया है। हालांकि, भारत 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। आपराधिक मामलों या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर विशिष्ट व्यक्तियों के प्रत्यर्पण या निर्वासन का उसका अपना इतिहास रहा है। वर्ष 1959 से भारत ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दे रखी है। चीन ने उसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन प्रत्यर्पण की मांग पूरी नहीं हुई। चीन से हमारे संबंध दोस्ती और कुश्ती वाले रहे हैं। चीन से गलवान-देपसांग झड़प भी हुई, तो उभयपक्षीय व्यापार एकदम से रुक नहीं गया। तो क्या हम बांग्लादेश से चीन जैसा सम्बन्ध बनाये रखना चाहते हैं, या फिर शेख हसीना की 'कूटनीतिक बलि' दे दी जाएगी? यह आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है, कि शेख हसीना किसी थर्ड कंट्री में शरण चाहेंगी। शेख़ हसीना की क़ीमत पर कोई तीसरा देश क्यों अपने सम्बन्ध तारिक़ रहमान सरकार से ख़राब करेगा? बीएनपी को इतना बड़ा जनादेश सहानुभूति वोट, और शेख हसीना शासन में हुए सितम की वजह से मिला है। तारिक़ रहमान हर हाल में शेख़ हसीना से पुराना स्कोर सेटल करना चाहेंगे।

प्रेरणा

धन का मूल्य संग्रह में नहीं, उसके संयमित उपयोग में है

मनुष्य के जीवन में धन का महत्व उतना ही है, जितना शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए शांति का होता है। धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम है, लेकिन जब यही माध्यम जीवन का उद्देश्य बन जाता है, तब वह सुख के बजाय चिंता और असंतोष का कारण बन जाता है। प्राचीन समय से ही संतों, ऋषियों और ज्ञानी पुरुषों ने मनुष्य को यह शिक्षा दी है कि धन कमाना गलत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के पुरुषार्थ और परिश्रम का परिणाम है। लेकिन धन का असीमित संग्रह और उसके प्रति अत्यधिक मोह मनुष्य के जीवन को असंतुलित कर देता है।

एक बार एक संत अपने आश्रम में शिष्यों को जीवन का सत्य समझा रहे थे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। संत के चारों ओर बैठे शिष्य उनकी वाणी को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। संत ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में धन का अर्जन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना धन के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। लेकिन धन का अर्जन करते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि धन साधन है, साध्य नहीं। यदि साधन ही साध्य बन जाए, तो जीवन का संतुलन समाप्त हो जाता है और मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाता है।

संत ने आगे कहा कि धन का उपयोग संयम और विवेक के साथ करना चाहिए। मनुष्य को उतना ही धन संग्रह करना चाहिए, जिससे उसका जीवन सम्मानपूर्वक चल सके और कठिन समय में उसे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन यदि धन का संग्रह केवल संग्रह करने के लिए किया जाए, तो वह मनुष्य के लिए बोझ बन जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने धन की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। उसे यह भय सताता रहता है कि कहीं उसका धन नष्ट न हो जाए या कोई उसे छीन न ले। इस प्रकार धन, जो सुरक्षा का माध्यम होना चाहिए, वही असुरक्षा और भय का कारण बन जाता है।

संत की इन बातों को सुनकर शिष्यों के मन में कई विचार उत्पन्न हुए। कुछ शिष्यों का मानना था कि यदि धन परिश्रम से अर्जित किया गया है और उसे सुरक्षित रखा जा सकता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उनका विचार था कि भविष्य अनिश्चित है, इसलिए जितना अधिक धन सुरक्षित रखा जाए, उतना ही अच्छा है। एक शिष्य ने संत से यही प्रश्न पूछा कि यदि कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ और मेहनत से धन अर्जित करता है और उसे सुरक्षित रूप से संग्रह करता है, तो इसमें क्या दोष है?

संत ने शिष्य की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि धन का संग्रह करना गलत नहीं है, लेकिन संग्रह के पीछे की भावना और उद्देश्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि धन का उपयोग न किया जाए और केवल संग्रहित किया जाए, तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाता। संत ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मधुमक्खियां दिन-रात परिश्रम करके फूलों से पराग एकत्र करती हैं और उससे शहद बनाती हैं। वे अपने जीवन का अधिकांश समय शहद के संग्रह में लगा देती हैं, लेकिन अंततः उस शहद का उपयोग अक्सर अन्य जीव और मनुष्य करते हैं। मधुमक्खियों का परिश्रम महान होता है, लेकिन वे अपने संग्रह का पूरा लाभ स्वयं नहीं उठा पातीं।

इसी प्रकार, यदि मनुष्य केवल धन के संग्रह में लगा रहता है और उसका उपयोग अपने जीवन या समाज के कल्याण में नहीं करता, तो उसका संग्रह भी अंततः व्यर्थ हो जाता है। धन का वास्तविक महत्व उसके उपयोग में है। यदि धन से किसी जरूरतमंद की सहायता की जाए, किसी दुखी व्यक्ति के जीवन में सुख लाया जाए या समाज के विकास में योगदान दिया जाए, तो वही धन सार्थक होता है। केवल संग्रहित धन, जो किसी के काम न आए, वह एक निर्जीव वस्तु के समान है, जिसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है।

संत ने आगे कहा कि धन के प्रति अत्यधिक मोह मनुष्य के मन को अशांत कर देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा में जीता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और वह अपने जीवन की वास्तविक खुशियों को भूल जाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति संयम और संतोष के साथ धन का उपयोग करता है, वह सीमित साधनों में भी सुखी और संतुष्ट रहता है। उसके मन में शांति होती है और वह अपने जीवन का आनंद लेता है।

मनुष्य को यह समझना चाहिए कि धन जीवन का एक हिस्सा है, संपूर्ण जीवन नहीं। जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और संतोष जैसे मूल्य धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि धन की प्राप्ति के कारण मनुष्य इन मूल्यों को खो देता है, तो वह वास्तव में गरीब हो जाता है, चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों न हो। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति सीमित धन में भी संतोष और संयम के साथ जीवन जीता है, तो वह वास्तव में धनी है।

संत ने यह भी कहा कि धन का एक अंश परोपकार में लगाना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करना और समाज के कल्याण में योगदान देना ही धन का सर्वोत्तम उपयोग है। ऐसा करने से मनुष्य को आत्मिक संतोष प्राप्त होता है, जो किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है। परोपकार से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसका जीवन सार्थक बन जाता है।

जीवन की सच्चाई यह है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। वह अपने साथ केवल अपने कर्मों का फल लेकर जाता है, धन नहीं। इसलिए धन का संग्रह करते समय यह स्मरण रखना चाहिए कि उसका उपयोग जीवन को सार्थक बनाने के लिए होना चाहिए। संयम और संतोष के साथ अर्जित और उपयोग किया गया धन ही वास्तविक सुख और शांति प्रदान करता है।

Rahul ने इधर US Trade Deal पर शाह की चुनौती की कबूल, उधर अमेरिका रवाना होने के लिए भारतीय टीम तैयार

भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का जिसको लेकर तरह-तरह की बातें कही जा रही है। आरोप है कि अमेरिका के सामने मोदी सरकार झुक गई। सरकार का कहना है कि राहुल गांधी इस बारे में भ्रम फैला रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी कि वो गुमराह करें कि यूरोपियन यूनियन इंग्लैंड इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचाया। राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं। किसी भी मंच तय कर लो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं। कांग्रेस इसी बहाने फिर से देश भर के किसान संगठनों को एकजुट करने में जुटी है। राहुल गांधी ने पंजाब और हरियाणा के कई किसान नेताओं से मुलाकात की है। मुद्दा अमेरिका के दबाव में रूस से सस्ता तेल ना खरीदने से लेकर किसानों के हितों की अनदेखी है। खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर। अमेरिका ने बांग्लादेश से भी व्यापार समझौता किया है। कांग्रेस के सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि अमेरिका से हुए समझौते के बाद भारत का क्या नुकसान है। तमाम आरोपों के बीच भारत अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील मार्च तक होने के आसार हैं। भारतीय टीम अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बार फिर से बयान दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच जो बटरल ट्रेड डील होने वाली है उसको लेकर बातचीत तय कार्यक्रम के हिसाब से आगे बढ़ रही है। खासतौर से अगले हफ्ते चीफ नेगोशिएटर के अध्यक्षता में एक टीम अमेरिका जा रही है और इस वक्त भी काफी कामकाज चल रहा है। खासतौर से जो डील होने वाली है उसको लेकर एक तरह से जो लीगल वेटिंग का काम चल रहा है लैंग्वेज पर कंट्रो के डील के उसके लीगल लैंग्वेज पर काम चल रहा है। निर्देश काम कर रहे हैं और तय कार्यक्रम के हिसाब से अह चीज़ आगे बढ़ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि इस डील को जल्द से जल्द अमली जमा पहनाया जाए। लेकिन अभी इसके जो टाइम लाइन है उसको लेकर अभी कोई कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर की जा रही है कि जो मिनी फ्रेमवर्क है यानी कि डील का जो पहला हिस्सा है वो अपने तय कार्यक्रम मार्च के पहले करने की पूरी कोशिश की जा रही है और मार्च तक होना संभव है। रही बात इजराइल और भारत के साथ डील वो भी कोशिश चल रही है और यूके के साथ जो डील लागू होने की बात है वो अप्रैल तक लागू हो जाएगी। जहां तक यूएस के साथ जो कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। खासतौर से एक बार सरकार ने फिर कहा है कि जीएम क्रॉप को बिल्कुल भारत में कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। बायो सिक्योरिटी को लेकर जो भी कंसर्न्स है उस कंसर्न्स को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कोई भी जीएम क्रॉप भारत में अंदर नहीं आएगी। तो अभी तक जो डील है उसको लेकर ये स्टेटस है और आने वाले दिनों में डील को डील को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत चल रही है।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने घोषणा की कि भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की कानूनी शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करेगा। इस समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर होने और लागू होने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव दर्पण जैन, जो वार्ता के लिए भारत के मुख्य वार्ताकार हैं, 23 फरवरी को वाशिंगटन के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वार्ता की प्रगति के बारे में अग्रवाल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच वर्चुअल बैठकें पहले से ही चल रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ वर्चुअल बैठकें चल रही हैं और अगले सप्ताह मुख्य वार्ताकार कानूनी समझौते के लिए कानूनी ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस पर काम अगले सप्ताह वाशिंगटन में जारी रहेगा।

उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका द्वारा हाल ही में जारी संयुक्त बयान में अंतरिम समझौते की व्यापक रूपरेखा दी गई है, जिसे अब कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते में बदलना होगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि संयुक्त बयान में समझौते की रूपरेखा निर्धारित की गई है। अब इस रूपरेखा को कानूनी समझौते में बदलना होगा, जिस पर दोनों पक्ष हस्ताक्षर करेंगे। इस महीने की शुरुआत में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की थी कि उन्होंने व्यापार को अधिक पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के उद्देश्य से एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है।

इस समझौते के तहत, भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि यह कटौती वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, जैविक रसायन, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी जैसे क्षेत्रों को कवर करेगी।

अभियान

उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर और भात पूजा का अद्भुत रहस्य

भारतीय ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपरा में ग्रहों का प्रभाव केवल आकाश तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू से उनका गहरा संबंध बताया गया है। नौ ग्रहों में मंगल ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसे साहस, ऊर्जा, शक्ति, भूमि, पराक्रम और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह अनुकूल स्थिति में होता है, तो वह व्यक्ति आत्मविश्वासी, साहसी और जीवन में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन जब मंगल की स्थिति प्रतिकूल होती है, तब उसे मांगलिक दोष या मंगल दोष कहा जाता है, जो जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। ऐसे में भारत में कुछ विशेष स्थान ऐसे हैं, जहां मंगल दोष के निवारण के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। इन स्थानों में सबसे प्रमुख और पवित्र स्थान मंगलनाथ मंदिर है, जो उज्जैन में स्थित है।

यह मंदिर शिप्रा नदी के पवित्र तट पर स्थित है और इसे मंगल ग्रह का जन्मस्थान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार मंगल देव का जन्म इसी पवित्र भूमि पर हुआ था, इसलिए यह मंदिर मंगल दोष निवारण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहां देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं, जो अपने जीवन में मंगल दोष से उत्पन्न समस्याओं से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां होने वाली अनोखी 'भात पूजा' है, जिसे अत्यंत प्रभावशाली और मंगल दोष को शांत करने वाला अनुष्ठान माना जाता है। भात पूजा का महत्व अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक है। इस पूजा में भगवान मंगल देव को चावल अर्पित किए जाते हैं। चावल की प्रकृति शीतल मानी जाती है और मंगल ग्रह की प्रकृति उग्र होती है। जब चावल अर्पित किए जाते हैं, तो यह मंगल देव के उग्र प्रभाव को शांत करने का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह पूजा मंगल दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और जीवन में संतुलन स्थापित करने में सहायक मानी जाती है। श्रद्धालु इस पूजा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और मानते हैं कि इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, पारिवारिक कलह समाप्त होती है और जीवन में सुख-शांति का आगमन होता है। मंगल ग्रह को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध भूमि, संपत्ति और भौतिक शक्ति से होता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उन्हें अक्सर विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में तनाव, क्रोध की अधिकता, आर्थिक समस्याएं और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए मंगलनाथ मंदिर में की जाने वाली भात पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। यह पूजा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और उसके जीवन में स्थिरता और संतुलन लाती है।

मंगलनाथ मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी अत्यंत विशेष है। यह स्थान प्राचीन काल से ही ज्योतिष और खगोल विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उज्जैन को प्राचीन भारत में समय और खगोलीय गणना का केंद्र माना जाता था। यहां से ही ग्रहों की गति और समय की गणना की जाती थी। इस कारण मंगलनाथ मंदिर का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह स्थान दर्शाता है कि भारत में प्राचीन काल से ही ग्रहों और उनके प्रभावों का गहन अध्ययन किया जाता रहा है। इस मंदिर में विशेष रूप से मंगलवार के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मंगलवार मंगल देव का दिन माना जाता है और इस दिन की गई पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। श्रद्धालु यहां आकर भात पूजा, अभिषेक और विशेष अनुष्ठान करते हैं। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है, जिससे श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है।

मंगल दोष के निवारण के लिए केवल मंदिर में पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना गया है, बल्कि कुछ अन्य उपाय भी बताए गए हैं, जो जीवन में मंगल के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक होते हैं। मंगल देव के इष्ट देव भगवान हनुमान को माना जाता है। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यह उपाय व्यक्ति के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गुड़, तांबे के बर्तन और लाल मसूर की दाल का दान करना भी शुभ माना जाता है। यह दान मंगल ग्रह को प्रसन्न करने और उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने का प्रतीक माना जाता है। साथ ही 'ॐ भौमाय नमः' और 'ॐ अंगारकाय नमः' मंत्र का नियमित जाप करने से भी मंगल दोष के प्रभाव कम होते हैं और व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करना भी मंगल दोष के निवारण का एक प्रभावी उपाय माना गया है। क्योंकि मंगल ग्रह का संबंध भूमि से है, इसलिए मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा करने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं और उनके अशुभ प्रभाव कम होते हैं। यह उपाय व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने में सहायक होता है।

जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में मंगल दोष के कारण समस्याएं आती हैं, उनके लिए मंगलवार का व्रत रखना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। कम से कम 21 मंगलवार तक व्रत रखने से मंगल दोष के प्रभाव कम होते हैं और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत के दौरान नमक का सेवन नहीं किया जाता और शाम को भगवान हनुमान को भोग लगाकर फलाहार किया जाता है। यह व्रत व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। मंगलनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहां आने वाले श्रद्धालु केवल पूजा ही नहीं करते, बल्कि अपने मन की शांति और आत्मिक संतुलन की भी प्राप्ति करते हैं। यह मंदिर लोगों को यह विश्वास दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान संभव है। आज के आधुनिक युग में भी इस मंदिर की महत्ता कम नहीं हुई है, बल्कि समय के साथ इसका महत्व और बढ़ता जा रहा है। देश-विदेश से लोग यहां आकर भात पूजा करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। यह मंदिर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और ज्योतिषीय ज्ञान का एक जीवंत उदाहरण है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर और यहां की भात पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यह स्थान लोगों को यह सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना केवल भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास से भी किया जा सकता है। जो श्रद्धालु सच्चे मन से यहां आकर पूजा करते हैं, उन्हें मानसिक शांति, आत्मिक संतुलन और जीवन में नई ऊर्जा की अनुभूति होती है। यही इस पवित्र मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता और इसकी अनंत आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

हर जिले में 'सीएम मॉडल कम्पोजिट विद्यालय' से बदलेगा शिक्षा का भविष्य

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में दो 'सीएम मॉडल कम्पोजिट विद्यालय' स्थापित किए जाएंगे। यह घोषणा राज्य के बुनियादी शिक्षा तंत्र को मजबूत करने, सरकारी विद्यालयों की छवि को सुधारने और छात्रों को निजी स्कूलों के समकक्ष, बल्कि उससे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। यह पहल केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य शिक्षा के पूरे स्वरूप को आधुनिक, तकनीकी और भविष्य उन्मुख बनाना है।

इस महत्वपूर्ण जानकारी को राज्य के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक विद्यालय के निर्माण और विकास पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता की अधोसंरचना, आधुनिक तकनीकी सुविधाएं और उत्कृष्ट शिक्षण वातावरण उपलब्ध हो। इस योजना का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों को केवल शिक्षा प्रदान करने का केंद्र नहीं, बल्कि समग्र विकास के आधुनिक संस्थान के रूप में विकसित करना है।

सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज में लंबे समय से एक धारणा रही है कि वहां संसाधनों और सुविधाओं की कमी होती है, जिसके कारण अभिभावक निजी विद्यालयों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन सरकार की इस नई योजना से इस धारणा को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल शिक्षण उपकरण, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, स्वच्छ और सुरक्षित परिसर तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इन विद्यालयों का वातावरण ऐसा होगा, जहां छात्र न केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि उनके व्यक्तित्व, कौशल और आत्मविश्वास का भी विकास होगा।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का मानना है कि यदि सरकारी विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं और उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इससे शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

भाषा के संदर्भ में भी सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा पांच तक और यथासंभव कक्षा आठ तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। इससे छात्रों को विषयों को बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिलती है और उनकी सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही, छात्रों को अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का भी ज्ञान दिया जाएगा, ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन सकें।

इस योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा के स्तर में मौजूद अंतर को कम करने में भी मदद मिलेगी। अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को सीमित संसाधनों के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। लेकिन मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी वही सुविधाएं मिलेंगी, जो बड़े शहरों के निजी विद्यालयों में उपलब्ध होती हैं। इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और देश के विकास में उनका योगदान बढ़ेगा।

इस दौरान सदन में पंचायत चुनाव प्रणाली से संबंधित विषय भी उठाया गया। पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट किया कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराने का निर्णय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर केंद्र सरकार से संवाद किया जा चुका है और भविष्य में इस दिशा में सकारात्मक निर्णय की उम्मीद की जा रही है। यह मुद्दा स्थानीय शासन व्यवस्था को अधिक लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाने से जुड़ा हुआ है।

कानून-व्यवस्था के विषय में भी सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है और अपराध दर में कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सुरक्षित वातावरण शिक्षा और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, और सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

सदन में प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। नेता प्रतिपक्ष और अन्य विधायकों ने अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन न उठाने की शिकायत की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि इस विषय पर सभी पक्षों की बात सुनने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। प्रशासनिक जवाबदेही लोकतंत्र की मूल भावना है, और इसे सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि जनता की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।

इस बीच समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने एक अभिनव सुझाव देते हुए कहा कि विधानसभा स्तर पर एक अधिकृत व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाना चाहिए, जिससे यदि कोई अधिकारी फोन न उठाए तो संबंधित विधायक उस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सके। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। यह सुझाव प्रशासनिक प्रणाली को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। 'सीएम मॉडल कम्पोजिट विद्यालय' योजना का व्यापक प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बेहतर शिक्षा से छात्रों को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके साथ ही, शिक्षित समाज अधिक जागरूक, जिम्मेदार और प्रगतिशील होता है, जो राज्य और देश के समग्र विकास में योगदान देता है।

इस योजना से सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ने की भी संभावना है। जब अभिभावकों को यह विश्वास होगा कि उनके बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिल सकती है, तो वे निजी विद्यालयों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इससे शिक्षा का बोझ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर कम होगा और उन्हें राहत मिलेगी।

इसके अलावा, इस योजना से शिक्षकों के लिए भी बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध होगा। आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों के साथ शिक्षक अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकेंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपने कार्य के प्रति अधिक समर्पित रहेंगे।

राज्य सरकार की यह पहल शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत है। यह योजना केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करेगी। यह कदम शिक्षा को अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

यदि इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया, तो यह उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है। यह पहल न केवल छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगी, बल्कि राज्य के समग्र विकास और प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। शिक्षा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है, और इस दिशा में उठाया गया यह कदम एक मजबूत, शिक्षित और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण की ओर एक ऐतिहासिक पहल साबित हो सकता है।

प्रेम विवाह की कीमत बनी जानः ससुराल में दामाद की निर्मम हत्या से दहला समाज

(जीएनएस)। लखनऊ की शांत मानी जाने वाली फिजा उस समय दहल उठी, जब रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करने वाली एक दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई। जिस घर को दामाद के लिए सम्मान और अपनत्व का स्थान माना जाता है, वहीं घर उसके लिए मौत का कारण बन गया। प्रेम विवाह से नाराज ससुराल पक्ष के लोगों ने कथित रूप से दामाद की पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस घटना ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि समाज के सामने यह गंभीर प्रश्न भी खड़ा कर दिया कि क्या आज भी प्रेम और व्यक्तिगत निर्णयों की कीमत इतनी क्रूरता से चुकानी पड़ती है। यह हृदयविदारक घटना काकोरी थाना क्षेत्र के लालताखेड़ा गांव की है, जहां 24 वर्षीय युवक रामसागर अपनी पत्नी को विदा कराने के उद्देश्य से अपने ससुराल पहुंचा था। वह अपने भाई राहुल के साथ उम्मीद और विश्वास लेकर आया था कि बातचीत से परिवार के बीच चल रहा तनाव समाप्त हो जाएगा और वह अपनी पत्नी को अपने साथ वापस ले जा सकेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा साबित होगी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रामसागर ने दिसंबर 2024 में गांव की रहने वाली कामिनी से प्रेम विवाह किया था। यह विवाह दोनों की आपसी सहमति और प्रेम का परिणाम था, लेकिन युवती का परिवार इस रिश्ते से संतुष्ट नहीं था। विवाह के बाद कुछ समय तक दोनों साथ रहे, लेकिन बाद में युवती के परिजन उसे अपने मायके ले गए। इसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। आरोप है कि युवती के परिजन उसकी दूसरी शादी कराने की तैयारी कर रहे थे, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई थी। रविवार को रामसागर अपने भाई राहुल के साथ ससुराल पहुंचा था, ताकि वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने साथ ले जा सके। गांव के बाहर स्थित एक बाग में दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन यह बातचीत जल्द ही विवाद में बदल गई। आरोप है कि युवती के पिता, उसके भाइयों और एक अन्य रिश्तेदार ने अचानक दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। पहले लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा गया और फिर चाकू से हमला किया गया, जिससे रामसागर गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हमला इतना क्रूर और अचानक था कि रामसागर को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उसका भाई राहुल, जो उसे बचाने के लिए आगे आया, उसे भी बेरहमी से पीटा गया। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए, जबकि दोनों भाई खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े रहे। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने रामसागर को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसका भाई राहुल गंभीर रूप से घायल है और उसका उपचार जारी है। यह घटना केवल एक हत्या नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता का प्रतीक है, जो आज भी प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं कर पाती। समाज के कुछ हिस्सों में आज भी पारिवारिक सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ऊपर रखा जाता है।

आधुनिक इंटरव्यू की कला सीखकर सफलता की ओर बढ़े विद्यार्थी, भगवान महावीर कॉलेज में हुआ प्रेरक सेमिनार

(जीएनएस)। सूरत के शैक्षणिक वातावरण में विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के एमबीए और एमसीए विभाग द्वारा 17 फरवरी 2026 को "मॉडर्न इंटरव्यू में महारत हासिल करनाः तैयारी से ऑफर तक" विषय पर एक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सेमिनार का सफल आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक इंटरव्यू प्रक्रिया की बारीकियों से परिचित कराना, उनके आत्मविश्वास को मजबूत बनाना और उन्हें नौकरी प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक रूप से तैयार करना था। आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में केवल शैक्षणिक योग्यता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इंटरव्यू में प्रभावी प्रस्तुति, आत्मविश्वास, संवाद कौशल और मानसिक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस सेमिनार का आयोजन किया गया।

इस सेमिनार का मार्गदर्शन प्रसिद्ध क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट जिग्नेश सांघवी ने किया, जिन्होंने विद्यार्थियों को इंटरव्यू की तैयारी से लेकर जॉब ऑफर प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया को सरल, व्यावहारिक और प्रभावी तरीके से समझाया। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि इंटरव्यू केवल प्रश्न और उत्तर का सत्र नहीं होता, बल्कि यह उम्मीदवार के व्यक्तित्व, सोचने की क्षमता, आत्मविश्वास और व्यवहार का समग्र मूल्यांकन होता है। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक तैयारी और सकारात्मक दृष्टिकोण। यदि उम्मीदवार अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित कर लेता है और अपने ज्ञान को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकता है, तो सफलता निश्चित होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास बढ़ाने की विशेष तकनीकों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू से पहले मानसिक रूप से स्वयं को सकारात्मक स्थिति में लाना, गहरी सांस लेना, अपने लक्ष्य की कल्पना करना और स्वयं पर विश्वास रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी समझाया कि नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना और सकारात्मक सोच विकसित करना इंटरव्यू में सफलता का महत्वपूर्ण आधार होता है। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को बॉडी लैंग्वेज, आंखों का संपर्क, बैठने का तरीका, बोलने का स्वर और चेहरे के भाव जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार की बॉडी लैंग्वेज उसके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को दर्शाती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

सेमिनार के दौरान विद्यार्थियों को इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। जैसे कि "अपने बारे में बताइए", "आपकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं", "आप हमारी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं" और "आपका भविष्य का लक्ष्य क्या है" जैसे प्रश्नों के उत्तर कैसे प्रभावी ढंग से दिए जाएं, इस पर व्यावहारिक सुझाव दिए गए। उन्होंने विद्यार्थियों को यह भी बताया कि उत्तर देते समय स्पष्टता, ईमानदारी और आत्मविश्वास बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंटरव्यू में केवल सही उत्तर देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।

इस सेमिनार की विशेषता यह रही कि यह पूरी तरह इंटरैक्टिव था। विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। सेमिनार के बाद विद्यार्थियों के लिए मॉक इंटरव्यू सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को वास्तविक इंटरव्यू जैसी परिस्थितियों का अनुभव कराया गया। इस मॉक इंटरव्यू सत्र के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर मिला। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें वास्तविक इंटरव्यू के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिली।

इस कार्यक्रम में कुल 52 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी विद्यार्थियों ने सेमिनार में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। विद्यार्थियों ने इस सेमिनार को अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि इस सेमिनार से उन्हें इंटरव्यू की तैयारी के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे भविष्य में इंटरव्यू का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे।

यह कार्यक्रम कॉलेज की डायरेक्टर डॉ. स्वेता आर. कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर दिया है और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल शैक्षणिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल और आत्मविश्वास भी विकसित करना आवश्यक है, ताकि वे अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकें।

इस कार्यक्रम के आयोजन में असिस्टेंट प्रोफेसर नेहल चोरावाला (टीपीओ) और असिस्टेंट प्रोफेसर खुशबू पटेल ने समन्वयक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस कार्यक्रम की योजना, समन्वय और संचालन में सक्रिय योगदान दिया। उनके प्रयासों के कारण यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और विद्यार्थियों को इसका भरपूर लाभ मिला।

सेमिनार के अंत में सभी प्रतिभागियों को ई-सर्टिफिकेट प्रदान किए गए, जिससे विद्यार्थियों का उत्साह और भी बढ़ा। यह सर्टिफिकेट उनके करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सहायक साबित होगा। इस सेमिनार ने विद्यार्थियों को न केवल इंटरव्यू की तकनीकी जानकारी दी, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी बनने की प्रेरणा भी दी।

इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों के करियर निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं और उन्हें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान महावीर कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित यह सेमिनार विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ, जिसने उन्हें अपने करियर के प्रति जागरूक और आत्मविश्वासी बनाया। यह कार्यक्रम न केवल उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में सहायक रहा, बल्कि उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करने में भी सफल रहा।

गगल एयरपोर्ट भूमि सौदे पर सख्ती: अनियमितताओं की जांच के लिए SIT गठन का ऐलान

(जीएनएस)। शिमला में स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार का दिन भूमि सौदों से जुड़े एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे के कारण विशेष रूप से चर्चा में रहा। कांगड़ा जिले के गगल एयरपोर्ट के प्रस्तावित विस्तार और ऊना जिले के गगरेट क्षेत्र में कथित रूप से हुई जमीन खरीद-फरोख्त में अनियमितताओं के आरोपों ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस गंभीर मामले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की इस घोषणा के साथ ही यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि सरकार भूमि से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता, बेनामी सौदे या अवैध लेन-देन को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यदि जांच के दौरान यह प्रमाणित होता है कि किसी व्यक्ति या समूह ने नियमों का उल्लंघन करते हुए जमीन खरीदी है या किसी प्रकार की दलाली अथवा धोखाधड़ी की है, तो ऐसी जमीन को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित व्यक्तियों को किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

यह मुद्दा विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान उस समय उठा, जब विधायक राकेश कालिया ने इस विषय पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि गगल एयरपोर्ट के आसपास और गगरेट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद-फरोख्त में अनियमितताएं हुई हैं और कुछ मामलों में बेनामी लेन-देन की आशंका भी जताई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग भी हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने विधायक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर की जाएगी। यदि जांच में किसी अधिकारी, दलाल या अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरक प्रश्न के दौरान विधायक राकेश कालिया ने एक पूर्व अधिकारी पर धोखाधड़ी के आरोप भी लगाए और कहा कि जांच प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे लोगों के मन में संदेह और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी मामले में देरी नहीं चाहती और जांच प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ सके और दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी व्यक्तियों द्वारा जमीन खरीदने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश भू-सुधार एवं भूमि अधिनियम की धारा 118 के तहत ही बाहरी व्यक्तियों को भूमि खरीदने की अनुमति दी जाती है। इस प्रक्रिया में सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और बिना अनुमति के की गई किसी भी जमीन खरीद को अवैध माना जाता है।

एआई युग में भारत की छलांग: 100 अरब डॉलर निवेश से बनेगा भविष्य का डिजिटल महाशक्ति आधार

(जीएनएस)। नई दिल्ली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश के प्रमुख औद्योगिक समूह अडाणी समूह ने वर्ष 2035 तक एआई अवसंरचना विकसित करने के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के विशाल निवेश की घोषणा की है। यह निवेश न केवल भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देगा, बल्कि देश को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में भी निर्णायक साबित हो सकता है। यह पहल केवल डेटा सेंटर निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, कंप्यूटिंग, क्लाउड, सर्वर निर्माण और डिजिटल सेवाओं के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने का एक समग्र प्रयास है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी 'एनर्जी-कंप्यूट' एकीकृत परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। इस निवेश के माध्यम से भारत में अत्याधुनिक, एआई-सक्षम और हरित ऊर्जा से संचालित डेटा केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जो भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेंगे। आज दुनिया तेजी से एक नई तकनीकी क्रांति की ओर बढ़ रही है, जिसे 'बुद्धिमत्ता क्रांति' कहा जा रहा है। जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और रोजगार के स्वरूप को बदल दिया था, उसी प्रकार एआई क्रांति पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और शासन प्रणाली को बदल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में, डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग क्षमता किसी भी देश की तकनीकी शक्ति और संप्रभुता का आधार बन गए हैं। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अडाणी समूह ने इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है।

इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी डेटा सेंटर हरित ऊर्जा स्रोतों से संचालित होंगे। इसका अर्थ यह है कि इन डेटा सेंटरों के संचालन के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह परियोजना सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप भी होगी। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन की चुनौती का सामना कर रही है, ऐसे में हरित ऊर्जा आधारित एआई अवसंरचना का निर्माण एक दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस पहल के परिणामस्वरूप भारत में एआई आधारित डिजिटल अवसंरचना का एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होगा, जिसकी कुल क्षमता लगभग 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना से सर्वर निर्माण, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग उपकरण और अन्य सहायक उद्योगों में लगभग 150 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश आकर्षित होने की संभावना है। इसका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक विकास पर पड़ेगा।

अडाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अडाणी ने इस पहल को भारत के तकनीकी भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जहां ऊर्जा और कंप्यूटिंग क्षमता का संयोजन ही किसी देश की वास्तविक शक्ति को निर्धारित करेगा। उनके अनुसार, आने वाले समय में वही देश वैश्विक नेतृत्व करेंगे, जिनके पास मजबूत एआई अवसंरचना और ऊर्जा संसाधन होंगे।

सोना-चांदी के वायदाओं में गिरावट जारीः सोना वायदा 1.51 लाख रुपये और चांदी वायदा 2.29 लाख रुपये के स्तर पर पहुँचा

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 256200.49 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 27646.12 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 228553.48 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 37388 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2688.37 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 20618.94 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 153551 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 153959 रुपये और नीचे में 151244 रुपये पर पहुंचकर, 154760 रुपये के पिछले बंद के सामने 1802 रुपये या 1.16 फीसदी गिरकर 152958 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 1238 रुपये या 0.98 फीसदी गिरकर 124845 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 197 रुपये या 1.24 फीसदी गिरकर 15631 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 151900 रुपये के भाव पर खूलकर, 152309 रुपये के दिन के उच्च और 149400 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 1853 रुपये या 1.21 फीसदी गिरकर 151024 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 154529 रुपये के भाव पर खूलकर, 154724 रुपये के दिन के उच्च और 152000 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 155220 रुपये के पिछले बंद के सामने 2082 रुपये या 1.34 फीसदी गिरकर 153138 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 235207 रुपये के भाव पर खूलकर, 237720 रुपये के दिन के उच्च और 229352 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 239891 रुपये के पिछले बंद के सामने 7453 रुपये या 3.11 फीसदी लुढ़ककर 232438 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 7397 रुपये या 3.04 फीसदी गिरकर 235834 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 7328 रुपये या 3.01 फीसदी घटकर 235924 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

▶▶ क्रूड ऑयल वायदा में 2 रुपये का नोमिनल सुधार : कमोडिटी वायदाओं में 27646.12 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 228553.48 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 20618.94 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37388 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 4731.62 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 31.05 रुपये या 2.59 फीसदी गिरकर 1167 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 1.7 रुपये या 0.53 फीसदी गिरकर 319.45 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 95 पैसे या 0.31 फीसदी की नरमी के साथ 306.75 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 50 पैसे या 0.27 फीसदी टूटकर 187.45 रुपये प्रति किलो हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2233.00 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5772 रुपये के भाव पर खूलकर, 5808 रुपये के दिन के उच्च और 5713 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 2 रुपये या 0.03 फीसदी की तेजी के संग 5793 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 5 रुपये या 0.09 फीसदी की तेजी के संग 5795 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 279.8 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 287 रुपये और नीचे में 274.2 रुपये पर पहुंचकर, 279.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 6.8 रुपये या 2.43 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 286.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 6.8 रुपये या 2.43 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 286.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 960.8 रुपये पर खूलकर, 40 पैसे या 0.04 फीसदी बढ़कर 960.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11652.40 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 8966.54 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4112.76 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 327.60 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 22.90 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 259.96 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 842.14 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1376.78 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.87 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.32 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8733 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61872 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 33293 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 437715 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 61344 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8541 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19712 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 65304 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 19984 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 21739 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 36900 पॉइंट पर खूलकर, 37599 के उच्च और 36900 के नीचले स्तर को छूकर, 575 पॉइंट घटकर 37388 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5800 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 1 रुपये की गिरावट के साथ 59.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.85 रुपये की बढ़त के साथ 15.85 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 445.5 रुपये की गिरावट के साथ 1022.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 240000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 3867.5 रुपये की गिरावट के साथ 7625 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 8.79 रुपये की गिरावट के साथ 10.2 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.71 रुपये की गिरावट के साथ 3.65 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 11.9 रुपये की गिरावट के साथ 16.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.6 रुपये की गिरावट के साथ 9.15 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 120.5 रुपये की बढ़त के साथ 1980 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 379.5 रुपये की बढ़त के साथ 1897.5 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.73 रुपये की बढ़त के साथ 4.8 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 20 पैसे की नरमी के साथ 0.9 रुपये हुआ।

‘स्वस्थ धरा, खेत हरा’ : गुजरात के 2.19 करोड़ किसानों मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित

▸▸ गुजरात में 19 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा ग्राम स्तर पर 26 निजी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत

▸▸ 2024-25 में एसएचसी पोर्टल के आधार पर 6,23,844 मिट्टी के नमूने एकत्रित, जिनमें से 6,23,295 नमूनों का हुआ विश्लेषण

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात के सर्वांगीण विकास में कृषि विकास एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। राज्य का सर्वांगीण कृषि विकास गुजरात सरकार की प्राथमिकता रही है। यदि खेती योग्य भूमि की समुचित देखभाल न की जाए, तो वह धीरे-धीरे बंजर बन जाती है। भूमि के बंजर होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण, भूमि में बढ़ती लवणता और रासायनिक उर्वरकों एवं दवाइयों का अत्यधिक इस्तेमाल आदि। गुजरात के अनेक क्षेत्रों में भी यह समस्या सिर उठा रही थी। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस समस्या के समाधान के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाते हुए वर्ष 2003-04 में ‘सॉइल हेल्थ कार्ड योजना’ यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (एसएचसी) लागू की। मिट्टी की सेहत की अहमियत को समझते हुए इस प्रकार की अनोखी योजना लागू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया।

प्रधानमंत्री की दूरदर्शी पहल को आगे बढ़ाते हुए और ‘विकसित भारत’ के विजन को ‘विकसित गुजरात’ के जरिए साकार करने की दिशा में सदैव अग्रसर रहा गुजरात मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मजबूत नेतृत्व में कृषि क्षेत्र मं निरंतर प्रगति कर रहा है। किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए तथा कृषि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक किसान-उन्मुख योजनाएं कार्यान्वित की हैं। ‘स्वस्थ धरा, खेत रहा’ मंत्र के साथ लागू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक गुजरात के 2.19 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

गुजरात में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का व्यापक क्रियान्वयन

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में वर्ष 2003-04 में लॉन्च की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की स्थिति के संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त करना था। एसएचसी योजना का पहला चरण 2003-04 से 2010-11 के दौरान और दूसरा चरण 2011-12 से 2015-16 के दौरान पूर्ण किया गया। पहले चरण में गुजरात के 43.03 लाख से अधिक किसानों और दूसरे चरण में लगभग 46.92 लाख से अधिक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क प्रदान किए गए। गुजरात में मिली सफलता के बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2015-16 में देश भर में ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना’ लागू की। जिसके अंतर्गत तीसरे चरण में वर्ष 2016-17 से अब तक राज्य के 1.25 करोड़ से अधिक किसानों को भारत सरकार की इस योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। पिछले एक दशक में, इस योजना के कारण किसानों को उनके खेतों में मिट्टी की पोषक स्थिति की कमी के बारे में पता चला है, साथ ही उन्होंने सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले उर्वरकों का उपयोग भी बढ़ाया है। अरवल्ली जिले के धनसुरा शहर के किसान बाबूभाई वसरामभाई पटेल ने बताया कि एसएचसी योजना के तहत उन्हें केवल आवश्यक खाद का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई, जिसका अनुसरण करने के फलस्वरूप उन्हें खाद का खर्च कम करने में मदद मिली। इस पहल से उनकी पैदावार बेहतर हुई और इनपुट लागत में भी कमी आई है।

क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत खेती योग्य भूमि की सेहत को बरकरार रखने के लिए निर्धारित पद्धति के अनुसार किसानों के खेत से मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं और उन्हें विश्लेषण के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाता है। जहां, नमूनों का विश्लेषण कर, सॉफ्टवेयर आधारित मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिट्टी में मौजूद विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा दर्शाता है, जिसमें वर्तमान में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, लौह तत्व, तांबा, मैंगनीज, बोरन, पीएच (अम्लता या क्षारीयता), ईसी (विद्युत चालकता) और ओसी (कार्बनिक कार्बन) जैसे कुल 12 तत्वों की मात्रा दर्शाई जाती है। इसके आधार पर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए किसानों को सही रासायनिक खाद के प्रयोग और उसकी सटीक मात्रा की वैज्ञानिक सिफारिश मुफ्त में मिलती है। इस प्रक्रिया से अनावश्यक रासायनिक खादों का अत्यधिक इस्तेमाल कम होता है और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में सहायता मिलती है।

सरकार प्रयोगशाला की क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए प्रयासरत

वर्ष 2024-25 में एसएचसी पोर्टल के आधार पर 6,23,844 मिट्टी के नमूने ऑनलाइन एकत्रित किए गए और 6,23,295 नमूनों का विश्लेषण किया गया। एसएचसी योजना के तहत वर्ष 2025-26 में भारत सरकार ने गुजरात के लिए 6,25,513 नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया है। गुजरात सरकार भी इस लक्ष्य को तय समय पर हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने अब तक 6,13,355 नमूने एकत्रित कर लिए हैं, जिनमें से 4,86,142 नमूनों का विश्लेषण पूरा हो चुका है। शेष नमूनों के परीक्षण का कार्य प्रगति पर है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तथा समय पर विश्लेषण करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं। अभी गुजरात में कृषि विभाग के अंतर्गत मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण के लिए कुल 19 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा 01 सूक्ष्म तत्व परीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला की क्षमता सालाना 10 से 11 हजार नमूनों का परीक्षण करने की है। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकारी सहायता से 26 निजी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं यानी ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। प्रत्येक निजी प्रयोगशाला भी सालाना 3,000 मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए तैयार है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को उनके खेतों की मिट्टी को प्रभावी ढंग से समझने और उसमें सुधार करने, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने, उत्पादकता बढ़ाने और उनकी भूमि के अनुरूप फसल उगाने में मदद करती है। इसके अलावा, यह योजना इनपुट लागत को कम करती है और आर्थिक लाभ में वृद्धि के साथ ही खेती के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देती है।

‘SITEX – 2026’ : सूरत बनेगा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब, 21 से 23 फरवरी तक मेगा एक्सपो

सूरत एक बार फिर वैश्विक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने जा रहा है। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सदर्न गुजरात चैंबर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में 21, 22 और 23 फरवरी 2026 को सरसाना स्थित सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में तीन दिवसीय ‘SITEX – सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो-2026’ का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह एक्सपो प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुला रहेगा और इसमें देश-विदेश की अत्याधुनिक टेक्सटाइल मशीनरी और तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि SITEX श्रृंखला की यह 13वीं और इस वर्ष की दूसरी प्रदर्शनी है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाना और आधुनिक तकनीकों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के एक्सपो से न केवल टेक्सटाइल उद्योग को नई दिशा मिलती है, बल्कि व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं।

चैंबर के वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला ने जानकारी दी कि इस एक्सपो में कई ऐसी मशीनों का प्रदर्शन होगा, जिन्हें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में पहली बार सूरत में लॉन्च किया जाएगा। इससे सूरत की पहचान एक टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली टेक्सटाइल सिटी के रूप में और मजबूत होगी। पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला ने बताया कि एक्सपो में हाई-स्पीड रैपियर लूम, एयरजेट, वॉटरजेट, पोजिशन प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी मशीनों के साथ वेलवेट एयरजेट मशीनरी के नवीनतम मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे।

इस एक्सपो का सबसे बड़ा आकर्षण दुनिया की पहली चार-शीट हाई-स्पीड रैपियर जैक्वार्ड मशीन होगी, जिसकी लंबाई 490 सेंटीमीटर है। इस मशीन की खासियत यह है कि इससे एक साथ चार साड़ियां बनाई जा सकती हैं। इससे उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि होगी और उत्पादन लागत में लगभग 25 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है। यह टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। इसके अलावा लगभग 9,500 डॉलर की कीमत वाली हाई-स्पीड एयरजेट मशीन का लाइव डेमो भी एक्सपो में प्रस्तुत किया जाएगा। यह मशीन अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध मशीनों की तुलना में अधिक किफायती और प्रभावी बताई जा रही है। इससे छोटे और मध्यम स्तर के टेक्सटाइल उद्योगों को आधुनिक तकनीक अपनाने में मदद मिलेगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रिंटिंग और एम्ब्रॉयडरी टेक्नोलॉजी भी इस एक्सपो का प्रमुख आकर्षण होगी। नई पोजिशन प्रिंटर मशीन 8 और 16 हेड वेरिएंट में उपलब्ध होगी और इसमें AI सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही 16 से 96 हेड तक की डायरेक्ट-टू-फैब्रिक प्रिंटर मशीनें, फॉइल मशीन मॉडल और अत्याधुनिक एम्ब्रॉयडरी मशीनों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। ये मशीनें डिजाइन की सटीकता बढ़ाने, उत्पादन समय कम करने और लागत घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

सर्कुलर निटिंग मशीनों की नवीनतम श्रृंखला भी इस एक्सपो में प्रदर्शित की जाएगी। सिंगल और डबल जर्सी सर्कुलर निटिंग मशीनें 34 डायमीटर और 28 गेज में उपलब्ध होंगी, जिनमें इंफ्रारेड नीडल ब्रेकेज डिटेक्टर और स्टिच लेंथ मीटर जैसे एडवांस फीचर्स होंगे। इससे उत्पादन की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होगा।

SITEX एक्सपो-2026 के चेयरमैन सुरेश पटेल ने बताया कि इस एक्सपो में सूरत, नई दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, अहमदाबाद, कोयंबटूर, पुणे, भीलवाड़ा और वलसाड सहित देश के विभिन्न औद्योगिक शहरों से 110 एग्जिबिटर्स भाग ले रहे हैं। यह एक्सपो टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े निर्माताओं, व्यापारियों और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म साबित होगा।

ऑनरेरी ट्रेजरर मितेश मोदी के अनुसार, इस एक्सपो के लिए अब तक 15,000 से अधिक विजिटर्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और कुल 25,000 से अधिक उद्योग से जुड़े लोगों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है। यह संख्या इस एक्सपो के महत्व और लोकप्रियता को दर्शाती है।

ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला ने बताया कि एक्सपो का उद्घाटन 21 फरवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे उषाकांत मारफतिया हॉल में किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह उद्घाटन समारोह टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।

जीवंत विरासत का शहर वडनगर बना संतुलित विकास का आदर्श मॉडल

▸▸ शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग की अधीनस्थ गुजरात शहरी विकास कंपनी के अंतर्गत ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार, सड़कों का विकास और तालाबों को आपस में जोड़ने जैसे विकास कार्य किए जाएंगे

▸▸ गायों के संरक्षण के लिए बनेगी देश की पहली भव्य वृंदावन गौशाला, जो ग्रामीण गौशाला विकास का बनेगी एक आदर्श मॉडल

▸▸ विद्युत विभाग के अंतर्गत भूमिगत विद्युतीकरण और सौरकरण के जरिए वडनगर का होगा कायापलट

▸▸ पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय में नजर आता है वडनगर का 2500 साल पुराना गौरवशाली इतिहास, प्रेरणा संकुल बना दुनिया का पहला अनुभवात्मक ज्ञान-आधारित शिक्षा केंद्र

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकास भी, विरासत भी’ के विजन को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार राज्य में ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का संतुलित मॉडल विकसित कर रही है। इसकी शानदार मिसाल है ऐतिहासिक शहर वडनगर। पुरातत्व, संस्कृति और इतिहास का जीवंत उदाहरण बन चुका वडनगर शहर लगभग 2500 साल पुराने सांस्कृतिक इतिहास को अपने में समेटे हुए है। पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का निर्माण हो या निर्माणाधीन देश की पहली भव्य वृंदावन गौशाला या फिर ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार कार्य, गुजरात सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण वडनगर आज एक टिकाऊ शहरी मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है।

पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय, प्रेरणा संकुल और आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

वडनगर के 2500 साल पुराने गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करने के लिए गत वर्ष पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह संग्रहालय भारत का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है, जो नए उत्खनन कार्यों से मिली वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में 5 हजार से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इतना ही नहीं, 9 विषयगत दीर्घाएं भी बनाई गई हैं, जो विभिन्न कालखंडों की कलाओं, शिल्पों और विभिन्न भाषाओं को प्रदर्शित करती हैं।

वहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिस स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, उस प्रेरणा स्कूल (संकुल) को भविष्य के आधुनिक शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा और नैतिक मूल्यों का अनूठा संगम है। यह दुनिया का पहला अनुभवात्मक ज्ञान-आधारित शिक्षा केंद्र है। इसके अलावा, वडनगर में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया गया है, जिसमें छात्रावास, कोच ऑफिस, रेक्टर क्वार्टर, आधुनिक रसोई घर, डाइनिंग रूम और रिक्रिएशन रूम जैसी सुविधाएं और सोलर सिस्टम एवं सीसीटीवी कैमरों जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल हैं।

विश्व स्तरीय हेरिटेज-टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है वडनगर

वडनगर में कीर्ति तोरण, शर्मिष्ठा तालाब, प्राचीन दरवाजों और किले की दीवारों (परकोटे) के अवशेष, हाटकेश्वर महादेव मंदिर और आसपास का क्षेत्र, बौद्ध मठ के पुरातात्विक अवशेष और ताना-रीरी स्मारक जैसे स्थलों के जीर्णोद्धार से शहर की समृद्ध विरासत जीवंत बन गई है। ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ शहर के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के गुजरात सरकार के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप वडनगर आज एक विश्व स्तरीय हेरिटेज-टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि वडनगर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जिसके अंतर्गत नॉमिनेशन डॉजियर और साइट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया गया है।

इन विकास कार्यों से वडनगर का होगा कायापलट

भव्य वृंदावन गौशाला : 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से देश की पहली भव्य ‘वृंदावन गौशाला’ का निर्माण किया जाएगा। गौशाला को ‘रूरल इनोवेशन हब’ के रूप में विकसित किया जाएगा और यह गायों के संरक्षण के लिए ग्रामीण गौशाला विकास का एक आदर्श मॉडल बनेगी।

तालाबों और जलाशयों को आपस में जोड़ने का प्रोजेक्ट : वडनगर में 40 से अधिक तालाबों को आपस में जोड़कर पानी को सहेजने और उसकी निकासी की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत तालाबों को गहरा और सुव्यवस्थित बनाकर उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक ग्रेविटी फ्लो सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे शहर के बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

हेरिटेज परिसर और फसाड डेवलपमेंट : प्रेरणा स्कूल परिसर, कीर्ति तोरण परिसर, पत्थर की हवेली और शर्मिष्ठा तालाब के आसपास के इलाकों में पारंपरिक स्थापत्य को संरक्षित रखते हुए फसाड (ऐतिहासिक इमारतों आदि का अग्रभाग) और हेरिटेज परिसर विकास के काम शुरू किए गए हैं, जिससे ऐतिहासिक इलाकों के सौंदर्य को चार चांद लग जाएंगे।

हेरिटेज रोड और जंक्शन विकास (फेज-2) : शहर की मुख्य सड़कों और जंक्शनों को हेरिटेज थीम के आधार पर विकसित किया जाएगा, जिससे यातायात प्रबंधन में सुधार के साथ ही पर्यटकों को सहज एवं बेहतर अनुभव मिलेगा।

भूमिगत विद्युतीकरण और सौरकरण : शहर में ओवरहेड विद्युत लाइनों को भूमिगत नेटवर्क में रूपांतरित किया जा रहा है। साथ ही, घरों और सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाकर वडनगर को ऊर्जा की दृष्टि से और अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

योजनाबद्ध पुनर्वास और स्लम रीडेवलपमेंट : योजनाबद्ध पुनर्वास कार्यों और स्लम रीडेवलपमेंट (झुग्गियों का पुनर्विकास) योजना के माध्यम से शहरी जीवन में सुधार लाया जाएगा।

भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) संपन्न: भारत की वैश्विक व्यापार सहभागिता में एक रणनीतिक उपलब्धि

(जीएनएस)। 16वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi एवं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम सुश्री Ursula von der Leyen द्वारा ऐतिहासिक घोषणा

विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ (जो वैश्विक जीडीपी का 25% हिस्सा है) के बीच विश्वसनीय साझेदारी का सुदृढ़ निर्माण

अभूतपूर्व बाज़ार पहुँचः भारत के 99% से अधिक निर्यात को यूरोपीय संघ में वरीयतापूर्ण प्रवेश, व्यापक विकास की संभावनाएँ

एमएसएमई, महिला, कारीगर, युवा एवं पेशेवरों के लिए नए अवसरों का सृजन

6.41 लाख करोड़ (75 अरब अमेरिकी डॉलर) के निर्यात को गति; वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लगभग 33 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात को विशेष लाभ

संतुलित एवं चरणबद्ध ऑटो उदारीकरण से “मेक इन इंडिया” को बढ़ावा

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के लिए अनुकूल बाज़ार पहुँच

संवेदनशील कृषि एवं डेयरी क्षेत्रों की सुरक्षा—कोई बाज़ार पहुँच नहीं

सेवाओं में महत्वाकांक्षी एवं वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बाज़ार पहुँच

कुशल एवं अर्ध-कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार

सीबीएएम (CBAM) प्रावधानों के माध्यम से रचनात्मक संवाद और सहयोग सुनिश्चित

भारत–ईयू एफटीए समावेशी, सुदृढ़ और भविष्य उन्मुख विकास की आधारशिला रखता है

माननीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम सुश्री Ursula von der Leyen ने आज 16वें भारत–यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (India–EU FTA) के संपन्न होने की संयुक्त घोषणा की। यह घोषणा भारत–ईयू आर्थिक संबंधों और प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ भारत की व्यापारिक सहभागिता में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ को खुले बाज़ार, पूर्वानुमेयता और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्ध विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करता है। वर्ष 2022 में वार्ताओं के पुनः प्रारंभ होने के बाद गहन चर्चाओं के उपरांत यह समझौता संपन्न हुआ, जो संतुलित, आधुनिक और नियम-आधारित आर्थिक साझेदारी की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यूरोपीय संघ भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। वर्ष 2024–25 में भारत–ईयू के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 11.5 लाख करोड़ (136.54 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा, जिसमें 6.4 लाख करोड़ (75.85 अरब डॉलर) का निर्यात और 5.1 लाख करोड़ (60.68 अरब डॉलर) का आयात शामिल है। सेवाओं का व्यापार वर्ष 2024 में 7.2 लाख करोड़ (83.10 अरब डॉलर) रहा।

भारत और यूरोपीय संघ क्रमशः विश्व की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं तथा वैश्विक व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं। इन दोनों विविध और पूरक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण अभूतपूर्व व्यापार एवं निवेश अवसरों का सृजन करेगा।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री Piyush Goyal ने माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता भारत की वैश्विक आर्थिक दृष्टि में एक निर्णायक उपलब्धि है। यह “मेक इन इंडिया” पहल को सुदृढ़ करेगा तथा 99% से अधिक भारतीय निर्यात को अभूतपूर्व बाज़ार पहुँच प्रदान करेगा।

यह समझौता वस्तुओं, सेवाओं, व्यापार उपायों, उत्पत्ति के नियम, सीमा शुल्क और व्यापार सुगमता जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ एमएसएमई और डिजिटल व्यापार जैसे उभरते क्षेत्रों को भी शामिल करता है।

वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग वस्तुएँ और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को निर्णायक प्रोत्साहन मिलेगा। लगभग 33 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर 10% तक के शुल्क शून्य हो जाएंगे।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चरणबद्ध एवं कोटा-आधारित उदारीकरण से “मेक इन इंडिया” और भविष्य के निर्यात को बल मिलेगा। भारतीय उपभोक्ताओं को उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त होगा।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र—जैसे चाय, कॉफी, मसाले तथा फल एवं सब्जियों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी। साथ ही डेयरी, अनाज, पोल्ट्री आदि संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

सेवाओं में आईटी, पेशेवर सेवाएँ, शिक्षा, वित्तीय सेवाएँ, पर्यटन एवं निर्माण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। यूरोपीय संघ के 144 उप-क्षेत्रों में भारतीय सेवा प्रदाताओं को पूर्वानुमेय पहुँच मिलेगी। गतिशीलता प्रावधानों के अंतर्गत इंट्रा-कॉरपोरेट ट्रांसफरी (ICT), व्यवसायिक आगंतुकों तथा अनुबंधित सेवा प्रदाताओं के लिए सुगम व्यवस्था की गई है। सामाजिक सुरक्षा समझौतों एवं छात्र गतिशीलता के लिए भी ढाँचा तैयार किया गया है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों को भी अवसर प्रदान किए गए हैं।

बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में TRIPS प्रावधानों को सुदृढ़ करते हुए दोहा घोषणा की पुष्टि की गई है तथा भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL) के महत्व को मान्यता दी गई है।

यह समझौता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करेगा।

भारत–ईयू एफटीए भारत की 22वीं एफटीए साझेदारी है। वर्ष 2014 के बाद भारत ने मॉरीशस, यूएई, यूके, ईएफटीए, ओमान और ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं।

यह समझौता “विकसित भारत 2047” के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को एक विश्वसनीय, गतिशील और भविष्य उन्मुख वैश्विक भागीदार के रूप में स्थापित करता है तथा समावेशी एवं सुदृढ़ विकास की आधारशिला रखता है।

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, अहमदाबाद में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

(जीएनएस)। कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) कार्यालय, अहमदाबाद में एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कर्मचारियों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, तनाव प्रबंधन के व्यावहारिक उपायों से परिचित कराना तथा स्वस्थ कार्य–जीवन संतुलन को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।

इस कार्यक्रम में डॉ. मनोज कुमार देव अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (मनोचिकित्सा) ने प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य में अधिक दक्ष होने के साथ-साथ व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भी बेहतर संतुलन बनाए रखता है। उन्होंने अवसाद, चिंता, कार्यस्थल तनाव एवं भावनात्मक थकान जैसी सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान, उनके प्रारंभिक लक्षणों तथा समय पर उपचार की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी। डॉ. देव ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर खुलकर चर्चा करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सहायता लेने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक कलंक (स्टिग्मा) को दूर करने पर जोर देते हुए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और उपचार को शारीरिक रोगों के उपचार जितना ही महत्वपूर्ण बताया। साथ ही कर्मचारियों को नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम, सकारात्मक सोच एवं संवाद को जीवनशैली का हिस्सा बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर उपस्थित मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति रेलवे प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि स्वस्थ एवं संतुलित मनोस्थिति ही उत्कृष्ट कार्य निष्पादन का आधार है। उन्होंने अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मानसिक स्थिति के प्रति संवेदनशील रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने पर बल दिया। प्रेरक उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने सकारात्मक सोच, संवाद एवं सहयोगात्मक कार्य संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए मानसिक तनाव, कार्यस्थल दबाव, पारिवारिक–व्यावसायिक संतुलन एवं परामर्श सेवाओं से संबंधित प्रश्न पूछे। विशेषज्ञ द्वारा दिए गए व्यावहारिक सुझावों को प्रतिभागियों ने उपयोगी एवं मार्गदर्शक बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोको निरीक्षक, कल्याण निरीक्षक तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। पश्चिम रेलवे द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम कर्मचारियों के समग्र विकास, सकारात्मक कार्य वातावरण एवं स्वस्थ कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं। रेलवे प्रशासन भविष्य में भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से कर्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है।

आईटी और बैंकिंग शेयरों की मजबूती से बाजार में लौटा विश्वास

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार ने सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भी मजबूती का प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया। निवेशकों के सकारात्मक रुख और प्रमुख क्षेत्रों में खरीदारी के कारण बाजार में उत्साह का माहौल बना रहा। विशेष रूप से बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और पूंजीगत वस्तुओं से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में आई तेजी ने बाजार को मजबूती प्रदान की और प्रमुख सूचकांकों को ऊंचे स्तर पर बंद होने में मदद की। यह लगातार दूसरा दिन रहा जब बाजार ने सकारात्मक संकेत दिए और निवेशकों के भरोसे को मजबूत किया।

कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 173.81 अंकों की बढ़त के साथ 83,450.96 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के दौरान सेंसेक्स ने 83,598 का उच्चतम और 82,987.43 का न्यूनतम स्तर छुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 42.65 अंकों की बढ़त के साथ 25,725.40 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की यह बढ़त इस बात का संकेत है कि व्यापक स्तर पर बाजार में खरीदारी का रुझान बना रहा और निवेशकों ने प्रमुख कंपनियों में निवेश जारी रखा।

विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार की इस तेजी के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख बैंकिंग और आईटी सेक्टर में निवेशकों की सक्रियता रही। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूत आधार मिला, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।